फैसला सुरक्षित

नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में

2015 का आपराधिक आवेदन संख्या 1016

उत्तराखंड राज्य ..... प्रार्थी

बनाम

भुवन चंद्र जोशी व अन्य... .... उत्तरदाताओं

श्री एस.एन.बाबुलकर, महाधिवक्ता ने राज्यध्याचिकाकर्ता के उप महाधिवक्ता श्री वी.के.जेमिनी की सहायता से सहायता प्राप्त की।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के वकील– श्री आर.एस. सम्मल,

प्रतिवादी संख्या 7 के वकील– श्री लोकेंद्र डोभाल,

के साथ

2015 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 145

भुवन चंद्र जोशी और अन्य ..... संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य... .... उत्तरदाताओं

संशोधनवादियों के वकील– श्री आर.एस. सम्मल,

श्री एस.एन.बाबुलकर, महाधिवक्ता ने राज्य के उप महाधिवक्ता श्री वी.के.जेमिनी की सहायता से सहायता प्रदान की।

प्रतिवादी संख्या 2 के वकील– श्री लोकेंद्र डोभाल,

माननीय रविंद्र मैथानी, जे।

इन दोनों मामलों में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए, इसे एक साथ लिया जा रहा है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है।

2. ये कार्यवाही प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल (संक्षेप में ''अपील'') की अदालत द्वारा 2012 के आपराधिक अपील संख्या 125, बलवंत सिंह चुफल और अन्य बनाम राज्य में पारित दिनांक 15.05.2015 के आदेश से उत्पन्न होती है। आक्षेपित आदेश द्वारा, एक आवेदन दायर किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 (संक्षेप में ''संहिता'') के तहत अभियोजन से वापस लेने के लिए खारिज कर दिया गया है।

3. 2015 के आपराधिक आवेदन संख्या 1016 में, राज्य ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है और 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 145 में, अपील के अपीलकर्ताओं ने संशोधन को प्राथमिकता दी है।

4. इस फैसले में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों को 2015 के आपराधिक मामले संख्या 1016 के संबंध में संदर्भित किया जाएगा।

5. विवाद पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा धारा 380, 454, 506 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच की गई और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा हल्द्वानी जिला नैनीताल के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। दिनांक 03.12.2012 के फैसले द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को धारा 380 और 454 आईपीसी के तहत आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके तहत सजा सुनाई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने 2012 की आपराधिक अपील संख्या 125 को प्राथमिकता दी, जिसमें संहिता की धारा 321 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अन्य बातों के साथ–साथ, इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रभारी अभियोजक ने अभियोजन से हटने के लिए अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने केवल सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वापसी के लिए आवेदन दायर किया।

6. इस मामले पर एक बार 09.01.2020 को सुनवाई हुई थी, जब इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"5. प्रतिवादी की ओर से, विद्वान वकील तर्क देंगे कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर एक आवेदन पर, राज्य सरकार ने लोक अभियोजक से टिप्पणियां मांगी हैं। इसके बाद, लोक अभियोजक ने एक आवेदन दायर किया जिसे अदालत द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी। यह तर्क दिया जाता है कि अदालत लोक अभियोजक की टिप्पणियों के संबंध में लोक अभियोजक से और विवरण प्राप्त कर सकती थी, जो नहीं किया गया था। वकील के अनुसार, राज्य सरकार ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर विचार किया और उचित विचार के बाद, अभियोजन से हटने का सार्वजनिक हित में निर्णय लिया। इसलिए, आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए।

6. विद्वान राज्य वकील प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील की ओर से दी गई दलीलों को अपनाता है।

7. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पेश वकील यह प्रस्तुत करेगा कि राज्य संहिता की धारा 321 के तहत अभियोजन से पीछे नहीं हट सकता है। यह अदालत की सहमति से स्वतंत्र रूप से लोक अभियोजक द्वारा किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामले में, कथित रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, नीचे दी गई अदालत ने आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अपने तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी नंबर 7 के विद्वान वकील ने बैरम मुरलीधर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 10 एससीसी 380 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बैरम (सुप्रा) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्योनंदन पासवान

बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 एससीसी 288 और अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 8 एससीसी 710 के मामले में निर्धारित बिंदु पर कानून पर विचार किया है।

9. बैरम मुरलीधर (सुप्रा) के मामले में, माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

"**18.** मुख्य प्रश्न यह है कि क्या लोक अभियोजक ने वास्तव में रिकॉर्ड पर सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर अपना न्यायिक विवेक लगाया है और खुद को संतुष्ट किया है कि अभियोजन से वापस लेने से सार्वजनिक हित के कारण की पूर्ति होगी या नहीं। इसे संक्षेप में निर्धारित किया जाना चाहिए। अब्दुल करीम मामले 1 में अदालत को एक सूचित सहमति देने की आवश्यकता है। अदालत की ओर से यह अनिवार्य है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि सामग्री से यह उचित रूप से माना जा सकता है कि अभियोजन वापस लेने से सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी। सामग्री का वजन करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि, अदालत की ओर से यह देखना आवश्यक है कि क्या सहमति देने से कानून के पाठ्यक्रम को रोका या दबाया जाएगा या प्रकट अन्याय होगा। संहिता की धारा 321 के तहत सहमति देते समय एक अदालत को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, और न्यायिक विवेक, जैसा कि कानून में तय किया गया है, का प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अदालत केवल एक मांग करने पर ऐसी सहमति नहीं दे सकती है। अदालत से यह उम्मीद की जाती है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करे ताकि यह देखा जा सके कि आवेदन नेक नीयत से दायर किया गया है और यह जनहित और न्याय के हित में है। 1– **अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 8 एससीसी 710** एक अन्य पहलू अदालत यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या इस तरह की वापसी न्याय के कारण को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए सावधानीपूर्वक और संबंधित विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ अपराध राज्य और समाज के खिलाफ हैं क्योंकि सामूहिक रूप से न्याय किए जाने की आवश्यकता है। इससे समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। लोक अभियोजक राज्य सरकार की ओर से डाकघर की तरह कार्य नहीं कर सकता है। उन्हें नेकनीयती से काम करने, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों का अध्ययन करने और एक स्वतंत्र राय बनाने की आवश्यकता है कि मामले को वापस लेने से वास्तव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी। इस संबंध में लोक अभियोजक पर सरकार का आदेश बाध्यकारी नहीं है। वह संहिता के तहत अपने वैध दायित्वों से बेखबर नहीं रह सकता है। उन्हें अदालत के प्रति अपने कर्तव्य के साथ–साथ सामूहिक रूप से अपने कर्तव्य को लगातार याद रखने की आवश्यकता है। (जोर दिया गया)

10. अभिलेखों से पता चलता है कि दिनांक 08.08.2014 को उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल को एक पत्र भेजा गया था जिसमें अभियोजन से हटने के राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया था और लोक अभियोजक, अपील के प्रभारी को न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हटने का निर्देश दिया गया था

(अनुलग्नक संख्या 3)। इसके अनुसरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक जिला सरकारी वकील (आपराधिक) ने 01.09.2014 को इस अनुरोध के साथ एक आवेदन दायर किया कि सरकार के निर्देशों के मद्देनजर, अपील वापस ली जा सकती है (अनुबंध संख्या 4)।

11. नीचे दी गई अदालत ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह देखा कि लोक अभियोजक ने अपनी स्वतंत्र राय नहीं दी कि अभियोजन से पीछे हटना क्यों आवश्यक है और आवेदन को खारिज कर दिया।

12. लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन से यह पता नहीं चलता है कि संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन दायर करने से पहले उनके द्वारा कोई टिप्पणी की गई थी या उनके द्वारा किसी भी सामग्री पर विचार किया गया था, न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रतिवादियों में से किसी ने ऐसी सामग्री दायर की है जिस पर लोक अभियोजक ने अभियोजन से हटने की राय बनाने से पहले विचार किया था। याचिकाकर्ता राज्य है, वह ऐसी सामग्री दायर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

13. अब्दुल करीम (सुप्रा) के मामले में, माननीय न्यायालय ने श्योनंदन पासवान (सुप्रा) के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी कीः **"18** धारा 321 के तहत आवेदनों के संबंध में आज जो कानून है, वह श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य 2 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में खालिद, द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें यह माना जाता है कि जब धारा 321 के तहत एक आवेदन किया जाता है, तो अदालत के लिए यह पता लगाने के लिए सबूतों का आकलन करना आवश्यक नहीं है कि क्या मामला दोषसिद्धि या बरी होने में समाप्त होगा। अदालत को यह देखना है कि क्या आवेदन नेक नीयत से, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किया गया है और कानून की प्रक्रिया को विफल करने या दबाने के लिए नहीं।

अदालत को मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद यह देखना होगा कि क्या आवेदन इस तरह की अनियमितताओं या अवैधताओं से ग्रस्त है जो सहमति दिए जाने पर स्पष्ट अन्याय का कारण बनेगा। जब लोक अभियोजक अपने समक्ष सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो अदालत को ऐसी सामग्री पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें और, इस तरह के विचार पर, या तो सहमति देनी चाहिए या सहमति से इनकार करना चाहिए। धारा का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अदालत को सहमति देते समय एक विस्तृत तर्कसंगत आदेश देना होगा। यदि सहमति देने वाले आदेश को पढ़ने पर, एक उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी सहमति उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर दी गई थी, तो सहमति देने वाले आदेश को अनिवार्य रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। धारा 321 में पर्यवेक्षी तरीके से अदालत द्वारा सहमति पर विचार किया गया है, न कि न्यायिक तरीके से। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक अभियोजक द्वारा स्वतंत्र विचार के बाद और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए वापस

लेने के लिए आवेदन ठीक से किया गया है। धारा 321 लोक अभियोजक को किसी भी आरोपी के अभियोजन से हटने में सक्षम बनाती है। धारा 321 के तहत प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार को केवल अदालत से उसके समक्ष सामग्री पर विचार करने पर सहमति से ही लागू किया जाता है। इस धारा को संतुष्ट करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि लोक अभियोजक ने नेक नीयत से काम किया है और उसके द्वारा विवेक का प्रयोग उचित है।

14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 इस प्रकार हैः अभियोजन से हटना–

किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से या तो आम तौर पर या किसी एक या अधिक अपराधों के संबंध में, जिनके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है और, इस तरह की वापसी,

(क) यदि यह आरोप तय किए जाने से पहले किया जाता है, तो आरोपी को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में आरोपमुक्त कर दिया जाएगा,

(ख) यदि यह आरोप तय किए जाने के बाद किया जाता है, या जब इस संहिता के तहत किसी आरोप की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में बरी कर दिया जाएगाः बशर्ते कि जहां ऐसा अपराध हो–

(i) किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध था, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है, या

(ii) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई थी, या

(iii) इसमें केन्द्रीय सरकार से संबंधित किसी संपत्ति का दुवनियोजन या विनाश या क्षति शामिल है, या

(iv) केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का इरादा रखते हुए किया गया था, और मामले के प्रभारी अभियोजक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, वह, जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, अभियोजन से हटने के लिए अपनी सहमति के लिए अदालत का रुख नहीं करेगा और अदालत, सहमति के अनुसार, अभियोजक को निर्देश देगी कि वह अभियोजन से हटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति को उसके समक्ष पेश करे।

प्रस्तर 15. इसके अवलोकन से पता चलता है कि यह लोक अभियोजक या सहायक अभियोजक, मामले का प्रभारी है, जो अदालत की सहमति से अभियोजन से हट सकता है।

कानून तय है कि लोक अभियोजक को उसके सामने रखी गई सामग्री पर अपनी स्वतंत्र राय बनानी होगी। अदालत को एक आवेदन पर निर्णय लेते समय सामग्री पर विचार करना होगा संहिता की धारा 321 के तहत। तत्काल मामले में, ऐसी सामग्री अदालत के समक्ष नहीं है।

प्रस्तर 16. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने से पहले, लोक अभियोजक के साथ–साथ राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सकता है कि वे इस न्यायालय के समक्ष उन सामग्रियों को प्रस्तुत करें, जिन पर लोक अभियोजक या राज्य सरकार द्वारा मामले से वापस लेने का निर्देश देने से पहले विचार किया गया था। अतः **निम्नलिखित निर्देशः–**

(i) श्री नवीन चन्द्र जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, जिला नैनीताल, जिन्होंने इस मामले में संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन किया था या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन करने से पहले उनके द्वारा किन सामग्री पर विचार किया गया था। 2012 की आपराधिक अपील संख्या 125 में, विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल की अदालत में 01.09.2014 को। (यदि किसी सामग्री को संवेदनशील माना जाता है, तो उसे अलग से एक सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है)।

(ii) श्री सुभाष चंद्रा, संयुक्त सचिव, उत्तराखंड सरकार, जिन्होंने दिनांक 08.08. 2014 को गृह विभाग–3, दिनांक 08.08.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल को पत्र लिखकर अभियोजन से हटने के सरकार के निर्णय से अवगत कराया और लोक अभियोजक, प्रभारी को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हट जाए या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को एक हलफनामा दायर करें। स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि यह निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार द्वारा किन सामग्री पर विचार किया गया था। कार्यालय नोटिंग के साथ पूरी फाइल (इससे संबंधित सभी संचार के साथ) को भी एक सीलबंद कवर में अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

(iii) उपर्युक्त हलफनामे/सामग्री 12.02.2020 को या उससे पहले दायर की जाएगी।

7. सहायक जिला सरकारी वकील, जिन्होंने संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन दायर किया, ने इस अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वापस लेने के आवेदन पर उनकी टिप्पणी मांगी गई थी और उन्होंने अभियोजन से वापस लेने के लिए कोई राय या सहमति नहीं दी थी।

8. श्री सुभाष चंद्रा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड सरकार ने भी एक हलफनामा दाखिल किया। संबंधित पैराग्राफ इसके अंतर्गत हैः–

"**5.** दिनांक 9.1.2020 के फैसले और आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि संबंधित राज्य वकील से कानूनी राय मांगी गई थी, जिसके द्वारा उन्होंने राय दी थी कि मामले को वापस लेना उचित नहीं होगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही प्रतिवादी (बलवंत सिंह चुफल) को दोषी ठहराया है। तथापि, बाद की तारीखों अर्थात् दिनांक 31–7–2014 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने मामले को वापस लेने का निर्देश दिया था। इस संबंध में इस माननीय न्यायालय (अनुबंध संख्या 1) के अवलोकन के लिए पूरे नोट शीट की फोटोकॉपी सीलबंद लिफाफे में दायर की जा रही है और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर मामला गृह विभाग को भेजा गया था और दिनांक 8.8.2014 को आरोपी ने पूरी फाइल संबंधित प्राधिकारी को अग्रेसित कर दी थी और उसके बाद संबंधित प्राधिकारी ने पूरी फाइल अग्रेसित कर दी थी। मामले को वापस लेने के लिए सहमति दी गई और दिनांक 23.7.2015 को यह भी संकल्प लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.5.2015 के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक आवेदन दायर किया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

9. अदालत ने राज्य के वकील से यह भी अनुरोध किया कि वह अभियोजन से वापस लेने से संबंधित पूरी फाइल नोटिंग अदालत के समक्ष पेश करें। फाइल नोटिंग भी प्राप्त हो गई है। वे बहुत ही खतरनाक तथ्यों को प्रकट करते हैं जिन पर थोड़ी देर में चर्चा की जाएगी।

10. विद्वान राज्य के वकील निष्पक्ष रूप से स्वीकार करेंगे कि अब सामने आए तथ्यों को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा दायर संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में कोई दम नहीं है।

11. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि संहिता की धारा 321 में राज्य संशोधन के मद्देनजर अभियोजन से वापस लेने की प्रक्रिया में राज्य की कुछ भूमिका है।

12. इस मामले में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नैनीताल के जिलाधिकारी ने अपने विचार रखे, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए अभियोजन वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव ने भी राय दी कि अभियोजन वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के विधि विभाग ने भी राय दी कि अभियोजन से हटना न्याय के हित में नहीं होगा। लेकिन, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अभियोजन से हटने का आदेश दिया।

13. ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता से न्यायालय की सहायता करने का भी अनुरोध किया कि क्या तंत्र तैयार किया

जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संहिता की धारा 321 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाए।

14. विद्वान महाधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि न्यायालय द्वारा तैयार की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया केवल एक तदर्थ तंत्र होगी। इसलिए, विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, न्यायालय हितधारकों को संहिता में दी गई प्रक्रिया का पालन करने के लिए चेतावनी दे सकता है।

15. यह संहिता की धारा 321 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न मामला है। तर्क दिया जा रहा है कि राज्य संशोधन को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में राज्य सरकार की भी भूमिका है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नीचे दी गई विद्वान अदालत ने संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रभारी अभियोजक/अभियोजन से हटने का स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। संहिता की धारा 321 के दायरे पर थोड़ा और चर्चा की जा सकती है।

16. संहिता की धारा 321, राज्य संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः– ''धारा 321 में ''किसी मामले के प्रभारी'' शब्दों के बाद ''उस आशय के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति पर (जो अदालत में दायर किया जाएगा)'' शब्द सम्मिलित किए जाएंगे– उत्तर प्रदेश अधिनियम 18, 1991। एस 3 (16–2–1991 से)।

17. राज्य संशोधन का प्रभाव यह है कि लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, मामले के प्रभारी, स्वयं, वापस लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसे राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी, जिसे अदालत में दायर किया जाएगा। राज्य संशोधन केवल प्रभारी लोक अभियोजक के आवेदन को वापस लेने के लिए एकमात्र अधिकार को प्रतिबंधित करता है। यह अनिवार्य करता है कि वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने से पहले, प्रभारी अभियोजक को राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी चाहिए और इसे अदालत में दायर करना चाहिए। लेकिन, किसी न किसी रूप में, संहिता की धारा 321 को किसी भी तरह से पढ़ा जाए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह प्रभारी अभियोजक है, जिसे एक राय बनानी है, राज्य सरकार से अनुमति लेनी है और आवेदन प्रस्तुत करना है।

18. तय कानूनी स्थिति से, यह पता चलता है कि संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन लोक अभियोजक द्वारा, अपने विवेक को लागू करने के बाद, सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर दायर किया जा सकता है। यह अच्छी बात है कि अभियोजन पक्ष से हटने से जनहित की पूर्ति होगी।

19. निस्संदेह, राज्य सरकार लोक अभियोजक को अभियोजन से हटने के लिए भी कह सकती है, लेकिन फिर यदि राज्य सरकार के पास कुछ सामग्री है जो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक को प्रदान की जानी है, तो अभियोजन से वापसी की अनिवार्यता के बारे में विचार करने और अपनी स्वतंत्र राय बनाने के लिए। लोक अभियोजक, मामले के प्रभारी, राज्य

सरकार से प्राप्त पत्र को न्यायालय में अग्रेषित करने के लिए डाकघर की तरह राज्य सरकार के दूत की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं।

20. इस मामले में शुरू में, जब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से दलीलें दी गईं, तो यह तर्क दिया गया कि नीचे दी गई अदालत लोक अभियोजक से एक रिपोर्ट बुला सकती थी कि क्या उसने अभियोजन से वापस लेने के लिए राय दी थी या नहीं। अब, यह किया गया है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अभियोजक, प्रभारी ने अभियोजन से हटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नाम वापस लेने के लिए कोई राय नहीं बनाई है। वास्तव में, उनकी राय इसके खिलाफ थी। अब, यह न्यायालय आगे यह प्रश्न देखना चाहेगा कि क्या गलत हुआ है।

21. राज्य सरकार से सीलबंद लिफाफे में प्राप्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। दिनांक 11.07.2013, यह सिफारिश करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के खिलाफ अभियोजन वापस ले लिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद इस पर रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट इस प्रकार हैं :–

(1) 04.10.2013 को प्रभारी अभियोजक ने राय दी कि अभियोजन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 से 6 को पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है और अपील लंबित है।

(2) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल ने 20.11.2013 को राय दी कि अभियोजन वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल ने 26.11.2013 को राय दी कि अभियोजन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

(4) 30.01.2014 को, प्रधान सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार ने राय दी कि अभियोजन से वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है और मामला तब बंद कर दिया गया था।

22. रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एक राजनीतिक दल के महासचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री से फाइल तलब करने और अभियोजन से वापस लेने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र पर, फाइल फिर से स्थानांतरित कर दी गई थी। पुन, गृह विभाग ने इस मामले को विधि विभाग, उत्तराखंड सरकार को भेज दिया है। विधि विभाग ने दिनांक 02.07.2014 को सिफारिश की कि कानून से हटना न्यायोचित नहीं है। गृह विभाग ने विधि विभाग की इस राय का समर्थन किया।

23. अभिलेखों से प्रतीत होता है कि इस बीच वही केन्द्रीय मंत्री, जिन्होंने 11.07.2013 को उत्तराखंड राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभियोजन से नाम वापस लेने की सिफारिश की थी, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। जब ये फाइल नोटिंग 31.07.2014 को उनके

समक्ष रखी गई थी, तो उन्होंने ''मामला वापस लिया जाना चाहिए'' का समर्थन किया और मामला वापस ले लिया गया।

24. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद, जो प्रभारी अभियोजक, नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी नैनीताल, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल, गृह विभाग और कानून विभाग, उत्तराखंड सरकार की राय के खिलाफ था, सरकार से अभियोजन से हटने के लिए एक पत्र लिखा गया था। प्रभारी अभियोजक ने सिर्फ राज्य सरकार के निर्देश का पालन किया, अपनी स्वतंत्र राय नहीं बनाई। उन्होंने वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया, लेकिन नीचे दी गई विद्वान अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।

25. अभियोजन से वापस लेने के लिए अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया मात्रा में बोलती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 321 के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का दंडमुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया था। मुख्यमंत्री ने 31.07.2014 को सभी की राय के खिलाफ अभियोजन से वापस लेने का आदेश दिया, जैसा कि कहा गया है। इससे पहले (प्रभारी अभियोजक से लेकर कानून विभाग और गृह विभाग तक ने राय दी कि अभियोजन वापस नहीं लिया जाना चाहिए)। मुख्यमंत्री ने ही दिनांक 11–07–2013 को केन्द्रीय मंत्री का पद धारण करते हुए उत्तराखंड राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री से अभियोजन से हटने की सिफारिश की थी। इसके बाद, जब वह 31.07.2014 को मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अभियोजन से हटने का निर्णय खुद लिया। कानून वापसी की अनुमति नहीं देता था। संविधान के तहत मुख्यमंत्री की भूमिका और जिम्मेदारी को भी परिभाषित किया गया है। एक मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उन्हें संविधान की अनुसूची III के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि ''और मैं बिना किसी भय और पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ सही काम करूंगा। (जोर दिया गया)

26. अदालत इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका, जिम्मेदारी या दायित्व (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढ़ती। विशेष रूप से, यह पता लगाने के लिए कि वह ''अभियोजन से वापस लेने'' का आदेश कैसे दे सकता है, जब उसे सलाह दी गई थी कि यह उचित नहीं हो सकता है। यहां तक कि अगर सरकार में किसी भी कार्य का नियम मुख्यमंत्री को प्रस्तुत राय के विपरीत निर्णय लेने की अनुमति देता है, तो इस तरह के नियम पर भी चर्चा की जाती, लेकिन यह अदालत निम्नलिखित कारणों से ऐसा करने से बचती है।

(i) मुख्यमंत्री की भूमिका, उत्तरदायित्व या दायित्व पर चर्चा करने से पहले, उसे एक दायित्व दिया जाना अपेक्षित है। सुनवाई का अवसर लेकिन चूंकि अभियोजन से हटने का आदेश देने वाले मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए इस मामले में उस विवाद में जाना न्याय के हित में समीचीन नहीं होगा। लेकिन इस न्यायालय का निश्चित मत है कि जब भी स्थिति की आवश्यकता हो, मुख्यमंत्री

को कानून का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाना चाहिए। आखिरकार, एक संवैधानिक लोकतंत्र में, कानून के शासन का सम्मान किया जाना चाहिए और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो अदालत को इसे लागू करने में संकोच नहीं करना चाहिए और दोषी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

(ii) इस मामले में विधि विभाग, उत्तराखंड सरकार ने विधि के उपबंधों के साथ–साथ मामले संबंधी कानूनों के संबंध में विस्तृत राय नहीं दी। विधि विभाग की राय कानून, मिसालों, नियमों और विनियमों पर आधारित होनी चाहिए। इस मामले में किसी कानून या केस कानून का हवाला नहीं दिया गया है। यदि ऐसा किया गया होता, तो मुख्यमंत्री को यह बताने के लिए बुलाया गया होता कि वह अदालत द्वारा निर्धारित कानून या कानून की अवहेलना कैसे कर सकते हैं।

27. मुख्यमंत्री अपने आप में कानून नहीं हो सकता। उन लोगों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है जो राजनीतिक नेताओं तक नहीं पहुंच सके। राजनीतिक नेता न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती हो सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री के अलावा किसी ने भी यह राय नहीं बनाई कि अभियोजन वापस लिया जाना चाहिए। प्रभारी अभियोजक ने अभियोजन से हटने के खिलाफ राय दी थी। मुख्यमंत्री का निर्णय किसी कानून पर आधारित नहीं है। न तो राज्य (मुख्यमंत्री को छोड़कर) और न ही प्रभारी अभियोजक ने अभियोजन से हटने के लिए कोई राय बनाई। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय का विचार है कि नीचे दी गई विद्वान अदालत ने संहिता की धारा 321 के तहत आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है और इस मामले में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तदनुसार, संहिता की धारा 482 के तहत याचिका और संशोधन दोनों को खारिज किया जाना चाहिए।

28. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए 2015 के आपराधिक आवेदन संख्या 1016 और 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 145 को खारिज किया जाता है।

29. मामले से अलग होने से पहले, न्यायालय अब संहिता की धारा 321 से संबंधित मामलों में निर्देश जारी करने की व्यवहार्यता पर विचार करता है।

30. सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने राज्य के विद्वान वकील से एक सवाल पूछा कि उन्होंने आक्षेपित आदेश को चुनौती क्यों दी, जबकि उनके पास सभी जानकारी थी कि प्रभारी अभियोजक ने कभी भी वापस लेने के लिए कोई राय नहीं बनाई है। अभियोजन पक्ष? कोई उत्तर नहीं दिया गया है। यह वास्तव में दुखद स्थिति है। यह स्थापित करता है कि राज्य जानबूझकर कि लागू आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है, संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को प्राथमिकता देता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस देश में सरकार

सबसे बड़ी वादी है। राज्य ने संहिता की धारा 482 के तहत जानबूझकर याचिका दायर की कि इसमें कोई गुण–दोष नहीं है। उन्होंने बस एक मौका लिया। यह न्याय प्रशासन के लिए बेहतर होता अगर याचिका दायर करने की अनुमति देने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता। चूंकि यह न्यायालय इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका की खोज नहीं कर रहा है, इसलिए यह न्यायालय भी इस पहलू को उत्तेजित नहीं करता है।

31. इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से अनुरोध किया कि वे न्यायालय की सहायता करें ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा सके कि संहिता की धारा 321 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा तैयार की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया केवल तदर्थ हो सकती है। इसलिए, उनके अनुसार हितधारकों को संहिता की धारा 321 के प्रावधानों का पालन करने के लिए आगाह किया जा सकता है। (पैराग्राफ 13 और 14 ऊपर के अनुसार)

32. यदि यह न्यायालय संहिता के उपबंधों के अनुरूप निदेश जारी करता है तो तदर्थ प्रक्रिया का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। ऐसे निर्देशों का बाध्यकारी प्रभाव होगा। मानव अधिकार बनाम सामाजिक कार्रवाई मंच के मामले में। भारत संघ, कानून और न्याय मंत्रालय (2018) 10 एससीसी 443, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश के मामले में जारी निर्देशों की वैधता का आकलन किया। शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 10 एससीसी 472, और इसके तहत देखा गयाः –

> **"37.....** निर्देशों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा परिवार कल्याण समितियों के गठन का निर्देश दिया है और समितियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया है। जैसा कि हम पाते हैं, समितियों के कर्तव्यों के निर्धारण और उसके लिए आगे की कार्रवाई संहिता से परे है और यह वास्तव में संहिता के किसी भी प्रावधान से नहीं आता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी प्रावधान का न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित कार्य होना चाहिए। विधायिका ने अपने विवेक से आईपीसी की धारा 498–ए के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर–जमानती बना दिया है। दोष जांच एजेंसी का है जो कभी–कभी बिना सोचे समझे कार्रवाई में कूद जाती है। अर्नेश कुमार **(अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273: (2014) 3 एससीसी (सीआरआई) 449)** मामले में जारी किए गए निर्देश धारा 41 सीआरपीसी और धारा 41–ए सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं। इसी तरह, जोगिंदर कुमार बनाम भारत, में दिशा–निर्देश बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 260: 1994 एससीसी (सीआरआई) 1172, और डीके। (बसु डी.के. बसु बनाम डब्ल्यू.बी. , (1997) 1 एससीसी 416: 1997 एससीसी (सीआरआई) 92) कोड के ढांचे और

जांच एजेंसी की पदानुक्रमित प्रणाली में अधिकारियों के अधीक्षण की शक्ति के भीतर हैं। इसका उद्देश्य यह देखना रहा है कि जांच एजेंसी शक्ति का दुरुपयोग न करे और लोगों को गिरफ्तार न करे।''

33. सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार (सुप्रा) के मामले में, अदालत ने आगे निर्देश जारी किए कि जांच अधिकारी जोगिंदर कुमार बनाम भारत के मामलों में बताए गए सिद्धांतों से सावधान और निर्देशित हों। उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 4 एससीसी 260,, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 एससीसी 416,, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 2 एससीसी 1, और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273,।

34. स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन से वापस लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह प्रभारी अभियोजक की स्वतंत्रता के साथ–साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसलिए, अदालत निम्नलिखित निर्देश जारी करती हैः–

(i) जब भी राज्य सरकार धारा के तहत अभियोजन से वापस लेने का निर्देश देती है। संहिता की धारा 321 के अनुसार ऐसी संपूर्ण सामग्री जिसके आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया है (जिसमें नाम वापस लेने के लिए सिफारिश पत्र, आसूचना एजेंसी की कोई रिपोर्ट आदि शामिल है) को भी प्रभारी अभियोजक को अग्रेसित किया जाना चाहिए।

(ii) विधि विभाग, उत्तराखंड सरकार, संहिता की धारा 321 से संबंधित किसी भी मामले पर राय देते समय, इस विषय पर न्यायालयों द्वारा निर्धारित सांविधिक उपबंधों के साथ–साथ सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। विधि विभाग कानून औरध्या दृष्टांतों पर राय का आधार बनाएगा।

(iii) प्रभारी अभियोजक राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई सामग्री के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाएगा। वह संहिता की धारा 321 के तहत केवल तभी आवेदन दायर करेगा जब वह संतुष्ट होगा कि अभियोजन से वापस लेने से सार्वजनिक हित के कारण की पूर्ति होगी।

(iv) प्रभारी अभियोजक अभियोजन से नाम वापस लेने के लिए अपनी राय के साथ राज्य सरकार से उसे प्राप्त संपूर्ण सामग्री न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। उसके अंदर आवेदन वह संक्षेप में यह भी निर्धारित करेगा कि उसने अपनी राय बनाने के लिए किस सामग्री पर विचार किया।

(v) यदि प्रभारी अभियोजक राज्य सरकार द्वारा उसे आहूत की गई सामग्री एकत्र करने के पश्चात् यह राय रखता है कि अभियोजन से नाम वापस लेना जनहित में नहीं है, तो वह अपनी राय सहित सामग्री राज्य सरकार को लौटा देगा।

(vi) यदि प्रभारी अभियोजक स्वयं यह विचार करता है कि अभियोजन वापस ले लिया जाना चाहिए, तो वह अभियोजन से हटने की अनुमति मांगते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह आधिकारिक रूप से सौंपी गई पूरी सामग्री भी प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर उसने ऐसी राय बनाई थी। एक बार राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, प्रभारी अभियोजक संहिता की धारा 321 के तहत पूरी सामग्री के साथ–साथ राज्य सरकार की अनुमति के साथ अदालत में आवेदन करेगा।

(vii) न्यायालय संहिता की धारा 321 के अधीन किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रभारी अभियोजक द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर भी विचार करेगा ताकि यह जांच की जा सके कि क्या आवेदन नेक नीयत से दायर किया गया है और यह किस प्रकार है? सार्वजनिक हित और न्याय। अदालत को यह देखने के लिए सामग्री पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वापसी न्याय के कारण को आगे बढ़ाएगी और कानून की प्रक्रिया को विफल या दबाने के लिए नहीं।

(vii) यदि प्रभारी अभियोजक उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन किए बिना संहिता की धारा 321 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे आवेदन पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

35. निर्णय की एक प्रति प्रमुख सचिव, गृह और प्रमुख सचिव, कानून, उत्तराखंड सरकार को भेजी जाए।

36. इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अपीलीय न्यायालय को भी भेजी जाए, जिसमें 2012 की आपराधिक अपील संख्या 125 पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया जाए। यदि सुविधाजनक हो, तो इसे दिन–प्रतिदिन के आधार पर सुना जा सकता है।

जितेन्द्र

(रवींद्र मैथानी)

27.05.2020